I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE, 1970

II. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL, 1970

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उपसभापति जी, यद्यपि सदन यह निर्णय ले चुका है कि आज ही इस बिल को लिया जायेगा और इस रेजोल्यूशन पर विचार तथा निर्णय हो जायेगा, मैं आप से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस निर्णय में मेरी असहमति है। मुझे इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि सोमवार को यह डिबेट क्यों नहीं हो सकती थी। मैं सदन के नेता से भी अपील करना चाहूंगा कि सदस्यों के भोजन की व्यवस्था करके सदन के समय को बढ़ाने और घटाने के साथ वह न चलें और अच्छा हो कि आज की इस योजना को भी वह स्थगित कर दें।

मैं आप की अनुमति से यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं: "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 फरवरी, 1970 को प्रख्यापित किये गये बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 (1970 का संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

यह अध्यादेश 14 फरवरी को जारी किया गया। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के अधिकरण के संबंध में जो पहले हम एक विधेयक यहां पर पास कर चुके हैं उस को खारिज कर दिया और उस के खारिज होने के बाद यह अध्यादेश जारी हुआ। इस अध्यादेश को जारी करते समय इस में यह कहा गया है कि : The President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्रपति महोदय को परिस्थितियों की ठीक से जानकारी नहीं करायी गयी। 10 तारीख को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के संबंध में अपना निर्णय दिया, रिजर्व बैंक द्वारा जो डाइरेक्टिव जारी किये गये, वह समाचार पत्रों में छपे हैं। स्टेट्समैन की एक कटिंग उध्दरण के रूप में मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। 10 फरवरी को ही बंबई की हेडलाइन्स न्यूज है :

> "In its directive, the Reserve Bank has asked the banks to seek its prior approval for advances in excess of Rs. 25 lakhs, investments in excess of Rs. 1 lakh in shares and debentures of joint stock companies and advances against such shares and debentures of over Rs. 5 lakhs.
>
> The Reserve Bank has taken over these powers in the public interest in terms of Section 35A of the Banking Regulation Act. The renewed directive also restricts the appointment and extension of services of the senior executives in the banks and expenditure on land or buildings above specified amounts as also making provisions and appropriations out of profits."

अर्थात बैंकिंग कानून के संबंध में बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अधिकार थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कानून को खारिज कर दिये जाने के बाद भी और रिजर्व बैंक पहले भी डाइरेक्टिव्स दे सकता था, उस कानून के निरस्त होने के बाद भी रिजर्व बैंक के उन अधिकारों में कोई फर्क नहीं आया और इसलिए यह कहना कि इम्मीडियेट ऐक्शन की कोई जरूरत थी इस बात का कोई आधार नहीं रहता। मेरा यही कहना था कि इन परिस्थितियों में इस आर्डिनेन्स को जारी करने के कोई बजूहात नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के कारण अनेकों अशोभनीय आलोचनायें इस देश में लोगों के द्वारा की गयी हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि संसद के कानून बनाने के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। संसद कानून बना सकती है, लेकिन जिस संविधान में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया उस संविधान ने हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की प्रस्थापना भी की है और संसद के द्वारा कानूनों का जि रूप में पारण होता है उस को रिव्यू करने का अधिकार, उस पर निगरानी रखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और अगर संसद केवल बहुमत के नशे में कोई भी ऐसी चीज यहां स्वीकार

कर ले जो संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती हो तो स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट को उस पर अपनी राय प्रकट करनी चाहिए। इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। अब यह बात अलग है कि हम संविधान की मर्यादायें क्या रखें। संविधान में संशोधन करना चाहे या न करना चाहें, लेकिन संशोधन की भी कोई सीमायें हैं। हमारे संविधान के कुछ ऐसे हिस्से हैं कि जिन में संशोधन करना संसद के लिए, बिना पंचवर्षीय चुनाव में उसी के आधार पर चुने जाने के बाद, उचित नहीं होगा। उन मूलभूत धाराओ में संसद ही संशोधन कर सकती है, लेकिन यह अधिकार संसद को जनता ही देगी। अगर इस प्रकार के मूलगामी परिवर्तन आप संविधान में करना चाहते हैं तो उस के लिए आवश्यक है कि हम जनता से उस शक्ति को प्राप्त करें। उसी के लिए हम चुनाव लड़ कर संसद में आयें और उस आधार पर हम उन मूलगामी परिवर्तनों को भी करें। मैं उस अधिकार को सुरक्षित समझता हूं, लेकिन महज इस वजह से कि हम ने बहुमत के नशे मे एक चीज कर डाली, संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें वह गलती बतायी और इतने मात्र से ही हम सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगायें या सारे संविधान को नष्ट करने की बाते करें, यह जनतंत्रीय परंपरा के अनुकूल नही है। यह तो वैसी ही बात होगी जैसे शेक्सपियर ने कई बार कहा है कि अगर कोई पाप करने से राजा की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो पाप कर लो, रानी बनते ही उस पाप को तुम पुण्य मे परिणत कर दो, अपराध समाप्त हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह चीज शेक्सपियर के नावेल्स के लिए तो ठीक है किन्तु किसी भी प्रकार के रूल आफ ला के लिए यह चीज शोभा नही देती। इस कारण उस प्रकार के आक्षेप सुप्रीम कोर्ट पर लगाने वाले लोगों को इस संबंध में पुनर्विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे देश में कोई घटना घटे, संसद में हम कोई चीज पास करें, सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार करे, न करे, वह हमारा अपना मामला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम देश के प्रधान मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित और संविधान के अंतर्गत मर्यादाओ में रहकर कानून बना कर सरकार चलाने का आश्वासन दिया है और मैं इसके लिए उनका आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि भगवान इस सारी राजनैतिक उथल-पुथल में भी उनकी संविधान के प्रति इस निष्ठा को बरकरार रखे, नही तो वह दिन इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और प्रजातंत्र की इस देश में क्या दुर्गति होगी यह कहना कठिन है। मैं यहां पर एक उद्धरण देना चाहूंगा, प्रावदा अखबार में इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो लाइन छपी है उसका मैं उद्धरण रखना चाहता हूं—

> "The struggle may touch upon the question of the country's constitutional structure."

प्रावदा अखबार में यह चीज छपी है। इसके पीछे क्या इम्पलीकेशन्स हैं, बाहर के देशों की इस देश की राजनीति में क्या गुल खिलाने की नीयत है इसको हमें बहुत सतर्कता से समझना चाहिए। एक सावरेन रिपब्लिक के आधार पर इस देश की सर्वोच्च सत्ता को हमें अपने हाथ में रखना है, किसी दूसरे देश के चौराहे पर गिरवी नही रखना है। हम किसी का राष्ट्रीयकरण करें या न करें, हम किसी चीज को किस हद तक सरकार के अधिकार में लेना चाहते हैं इसका फैसला हम करें। महज इस वजह से कि हमें संविधान की मर्यादा में किसी सीमा से आगे बढ़ने का अधिकार नही है, दूसरे देश हमारे सारे संवैधानिक ढांचे को उलटपुलट कर उसमें से संधि प्राप्त करें, यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

इस भूमिका के आधार पर हमें इस निर्णय पर विचार करना चाहिए। यह जो आर्डिनेन्स जारी किया गया है और जिसके आधार पर बिल विचाराधीन है इस सदन में, मैं समझता हूं कि उन सब चीजों का उसमें समावेश कर लिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मे थी। अभी तक मैं सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार पर अपनी राय नही देना चाहूंगा। यह ज्यादा अच्छा होता अगर सरकार इस बिल को लाने के पहले, इस

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

आर्डिनेन्स जो जारी करने के पहले कम से कम रिजर्व बैंक आफ इंडिया की राय जरूर ले लेती कि रिजर्व बैंक अब इस परिस्थिति में जो अधिकार उसके पास है या जिस तरह का कारोबार चल रहा है उसके अंतर्गत क्या वह इस कानून की आवश्यकता इसी रूप में चाहता है या नहीं चाहता है । इस आधार पर हम इस कानून को लाते । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय इस बात को यहां बताएं कि रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध मे क्या राय दी और क्या उसकी दी हुई राय को यहां पर सदन के पटल पर रख कर हम सब लोगों को अवगत कराएंगे क्योंकि रिजर्व बैंक एक फाइनेंशियल अथारिटी है, देश की फिसकल पालिसीज़ को गाइड करने में वह क्या गाइड लाइन दे सकती है उससे हमको इन नीतियों को समझाने में मदद मिलेगी ।

पुराना आर्डिनेन्स जारी करने के बाद, अपना फैसला करने के बाद नया आर्डिनेन्स जारी करने और नया बिल पेश करने मे 8 महीने का समय सरकार को मिला । जब जब पिछले दिनो में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे मे सवाल पूछे गए, तो सरकार की तरफ से यह जवाब दिए गए कि सब मामला बिलकुल तैयार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दो, उसके बाद हम खटाक से देश के सामने वह नीति रखेंगे । मने समाचारपत्रों में पढ़ा है---शायद मंत्री महोदय ने कहा कि अभी 6 महीने का समय और दो, 6 महीने मे हम सारी स्कीम बना कर आपके सामने रख देंगे । मैं समझता हू कि सरकार ने फिर से वही गलती की है । उस सारी स्कीम को बना कर किस आधार पर वह चलाना चाहती है, किस तरह से इस सारे बैंकिंग के काम का निर्धारण करना चाहती है, यह अभी बनाना बाकी है और इसीलिए मैं उनको कुछ तथ्य देना चाहता हूं । सारी नीति निर्धारित करते समय वे विचार करना चाहें तो उनका उपयोग वे कर सकते हैं ।

मैं इस बात को यहां पर रख देना चाहूंगा कि अभी भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाई गई सारी आपत्तियों को पूरा नही किया है । अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रहने देगा या नही रहने देगा इसका वे विचार कर लें । विशेषकर विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में सरकार कोई निर्णय नही कर पाई । विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने या न करने के सम्बन्ध मे सरकार ने मौन धारण किया हुआ है । मंत्री महोदय ने तर्क दिए हैं कि हम अपने दरवाजे बन्द नही करना चाहते, विदेशों से हमारे सम्बन्ध है, विदेशी व्यापार बढ़ता है । यह तो ठीक है लेकिन इससे अगर उनकी यह मंशा हो कि भारत के बैंकों को हिन्दुस्तान के विदेशी व्यापार को अपने हाथ में नही लेना चाहिए तब तो मैं समझता हूं कि वह हिन्दुस्तान के साधारण व्यवसाय में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करना चाहते हैं । यह बात सच है कि हमारे कुछ बैंक बाहर के देशो में हैं, लेकिन वह 3-4 देश हैं । अगर रेसीप्रोसिटी का ही विचार करना था तो उन चार देशों में, जिनमें भारत के बैंकों की शाखाएं हैं, उनको छोड़ देते, बाकी बैंकों को पहले ले लेते । एक मिसाल तो कायम करते कि हम इन बाहर के विदेशी बैंकों के बारे में विचार करने की हिम्मत कर सकते है । उन्होंने कहा कि इन 14 बैंकों का अधिग्रहण एक बार कर लिया जाय तो कोई कारण नही कि बाकी के बैंकों का विचार न किया जाय । तो मेरा यह कहना है कि उन चार देशों को छोड़कर बाकी फारेन बैंक्स का अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू करिए और एक्सपेरीमेंट सफल हो तो बाकी बैंकों का भी अधिग्रहण करिए । विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने के लिए किसने सरकार पर चाबी घुमा रखी है, सरकार के ऊपर किसका भय है, किसकी राजनीति काम कर रही है जिसके कारण यहां विदेशी बैंकों को आप हाथ लगाने का साहस नही कर रहे ?

बैंकों के अधिग्रहण के समय एक बहुत बड़ा तर्क दिया गया कि इस अधिग्रहण के बाद गरीब लोगों को, किसानों को, छोटे तबके के लोगों को, छोटा काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलेगा । इस प्रकार के तर्क दिए गए है । बाकी 14 बैंकों की अलग अलग क्या इस मामले में रिपोर्ट रही है उसके मेरे पास आंकड़े नही हैं,

स्टेट बैंक आफ इंडिया के बारे में मेरे पास आंकड़े हैं । 1969 में इस बैंक के कुल आउटस्टेंडिंग एडवान्सेज़ थे 779.9 करोड , बैलेन्स टुवर्डस फार्मर्स 91.9 करोड़ यानी 11 परसेंट । 66 per cent of this amount is seasonal because it is crop-loan. एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स–18 लाख, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ 121 करोड़, स्माल ट्रेडर्स–7.2 करोड । 1969 में स्टेट बैंक आफ इंडिया के एग्रीगेट डिपोजिट्स में 133 करोड़ की बढ़ोतरी हुई अर्थात केवल 14.8 परसेंट लेकिन 1968 में इसी पीरियड में 140 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो 18.6 परसेंट थी । डिमान्ड डिपोजिट्स इस बार 12.7 परसेंट बढ़े जबकि कारेस्पोंडिगली पिछले साल 15.4 परसेंट बढ़े थे । टाइम डिपोजिट्स इस साल 18.6 परसेंट बढ़े हैं जबकि पिछले साल 21.7 बढ़े । इसमें से कुल मिला कर यह मानना पड़ेगा कि डिपाजिटस घटे हैं और इसमें से एडवांसेज़ बढे हैं । अब यह जो एडवांसेज़ बढ़ने की परिस्थिति पैदा हुई उसके लिये इसमें शक नहीं कि बहुत बड़ा वातावरण का निर्माण किया गया, आशायें बांधी गई और आशायें बंधने से जगह जगह से मांग हुई, बैंकों से भिन्न भिन्न प्रकार से लोग मदद मांगने लगे लेकिन बैंक्स की फाइनेंशल पोजीशन पर क्या परिणाम हुआ । इसका परिणाम हुआ, अगर मैं बाकी सारे बैंकों की बात करूं तो उन्हें स्टेट बैंक से और स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक से बारोइंग पर रिजार्ट करना पड़ा है । ये बारोइंग्स बहुत बढ गई रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी नेशनलाइज्ड बैंक्स को लगभग 45 परसेंट बारो करना पड़ा है, लास्ट ईयर केवल 15 परसेंट बारोइंग्स थी रिजर्व बैंक से, एकदम तीन गुना बारोइंग्स की संस्था बढ़ गई ।

टाइम डिपाजिट 75 करोड़ बिटवीन अक्टूबर एंड जनवरी की अवधि में बैंकों के बढे लेकिन बारोइंग्स 145.97 करोड़ बढ़ गई, जब कि पिछले साल कुल 13 करोड़ की थी ।

कुल मिलाकर इसका नतीजा यह हुआ है कि रिजर्व बैंक से ज्यादा रकम मांगी जाने लगी है । जो अपेक्षा आपने की थी डिपाजिट्स की इन बैंकों के अधिग्रहण के समय वह पूरी नही हुई, आपने 400 करोड़ के इंक्रीज़ की आशा की थी लेकिन आगे चल कर 1969 ई० में कुल 203 करोड़ के डिपाजिट्स बढे । अब इसका मतलब यह है कि आपकी अपेक्षायें जो डिपाजिट्स की थीं वह घटी हैं और आपके जो एडवांसेज़ हैं वह बढ़े हैं ।

इसी में से एक विचित्र परिस्थिति का निर्माण हुआ, जैसा कि 18 फरवरी को श्री एल० के० झा ने जो डिसीशन एनाउंस किया है बम्बई में— after reviewing the credit trends in the current busy season at a meeting with the chairman, custodians, and chief executives of major banks.
उसमें उन्होंने कहा :

> "In terms of the latest decision, scheduled commercial banks will be entitled to refinance at concessional or bank rates only up to the extent of the increase, over the base period (corresponding quarter of last year) of their outstanding credit to exports, direct advances to agriculture and small scale industries covered by the guarantee of the Credit Guarantee Organiation."

तो जो जो आशायें पैदा की थी उससे रिजर्व बैंक मे बारोइंग्स बढ़ते ही रिजर्व बैंक के द्वारा क्रेडिट स्क्वीज आ गया और उसका एक ज्वलंत प्रमाण है कि इतने दिनों तक, पिछले कुछ महीनों तक, इन सारे बैंक्स की लिक्विडिटी 29 परसेंट थी, बीच में 30 परसेंट कर दी गई और अब सब बैंक्स को कहा गया है कि अप्रैल के एंड तक 31 परसेंट तुम अपनी लिक्विडिटी जमा करावो । अब, यह साधारण चीज़ नहीं है, 1 परसेंट लगता है लेकिन इस लिक्विडिटी का 1 परसेंट का परिणाम स्टेट बैंक पर यह हुआ कि 22 करोड़ रुपया जो उनको एडवांस कर रखा है वह विदड्रा कर के रिजर्व बैंक में जमा करवाना पडेगा, जो सेंट्रल बैंक आफ इंडिया है उस पर 8 करोड़ रुपये का परिणाम होगा, जो बैंक आफ इंडिया है उस पर 6 करोड़ का और पंजाब नेशनल बैंक पर 4 करोड़ रुपये का परिणाम होगा इस 1 परसेंट लिक्विडिटी को बढ़ाने का ।

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

मैं समझता हूं कि इसी का नतीजा है कि इन सारे बैंक्स ने अपने सब सेक्टर्स में फाईनेंसिंग करना बन्द कर दिया है, प्रायरिटी सेक्टर में भी उन्होंने रुपया देना बन्द कर दिया, एडवांस एप्लीकेशंस लेना उन्होंने बन्द कर दिया यह कह कर कि हमारे पास पैसा नही है, हम दे नहीं सकते और इसका सबसे ज्यादा परिणाम किसानों पर पड़ा । यह समय है जब कि किसानों को फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिये पैसा चाहिये, यह समय ऐसा है जब कि किसानो को पैसा चाहिये अपनी फसल की भूमि को आर्थिक दृष्टि से बनाने के लिये और इसी समय सारे बैंक्स को डेड कर दिया है, लिक्विडिटी का परसेंटेज बढ़ा कर और आज उनके पास एडवांस करने के लिये कुछ नहीं रहा है ।

इस समय एक और नई आवश्यकता है और वह है एडवांस टैक्स पेमेंट्स की, उसके लिये आज लोगों को पैसा चाहिये । एडवांस टैक्स पेमेंट्स के लिये बैंकों से इस समय सहायता लेना उनके लिये आवश्यक है, परन्तु बैंक उनकी मदद नहीं कर रही हैं । इसलिये यह जो परिस्थिति है, उसका नतीजा यह हुआ है कि जिन लोगों को हम मदद देना चाहते थे, उनको हम मदद नही दे पा रहे है ।

मैं यहां पर जो वीक एंडिंग सिक्स्थ मार्च की बैंकों के परिणाम पर एक रिपोर्ट है, वह मैं आपके सामने उधृत करना चाहता हूं :

During the week ended March 6, banks' borrowings from the Reserve Bank have come down by Rs. 7.52 crores to Rs. 214.59 crores. Thus, in the three weeks ended March 6, these borrowings have declined by Rs. 12.62 crores. Banks have also drawn down their deposits with the Reserve Bank from Rs. 170.57 crores to Rs. 161.27 crores.

During the week ended February 27, credit by scheduled commercial banks expanded by Rs. 13.11 crores to Rs. 3,875.10 crores. Their demand deposits declined by Rs. 1.92 crores to Rs. 2,152.82 crores while their time, deposits moved up by only Rs. 52 lakhs to Rs. 2,798.53 crores. Their investment came down from Rs. 1,187.03 crores to Rs. 1,180.61 crores.

मेरा यही निवेदन है कि इस समय जब कि हम फिर से इस कानून को बनाने जा रहे है, तो यह अच्छा होता कि इसकी सारी वर्किंग की रिपोर्ट यहां रखी जाती । सारी वर्किंग की रिपोर्ट को छः महीने के बाद मंत्री जी सदन के सामने रखने की बात कर रहे हैं । यह बात सच है कि नया कानून फिर से 1970 के नाम से आया है, परन्तु यहां पर श्री बी० के० पी० सिंहा के द्वारा यह तर्क दिया गया, जब मैंने इस पर पूर्ण विचार की मांग की कि यह रेपलिका है, जो पहले कानून पास कर चुके वही कानून कानून फिर से आ रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम मिनिस्ट्री इस कानून के इम्प्लीकेशंस को वर्क आउट नही कर पाई और आज भी छः महीने का समय चाहती है, इसको वर्क आउट कर के टबिल पर रखने के लिये । इसीलिये मेरा कहना है कि पहले तो राजनैतिक कारण था, मोरारजी देसाई को मंत्रिमंडल से गिराना था, मोरारजी देसाई के इंडिविजुअल विंडिक्टिव कदम के बारे में एक बहुत बड़े घटाटोप राजनैतिक आवरण का निर्माण करना था और उस जल्दबाजी में बैंकों का अधिग्रहण किया और अब शायद नाक का सवाल हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके अधिग्रहण के कानून को निरस्त कर दिया और अब नाक की लाज बहुमत के आधार पर रह सकती है, परन्तु यह कदम ऐसा है—पहले भी मैंने कहा था और आज भी कहते हैं कि यह कदम देश की सारी क्रेडिट और करेंसी पालिसीज़ के साथ जुडा हुआ है, इससे देश में इंफ्लेशन, इससे देश में प्राइस स्टैबिलाइजेशन और इससे देश की अनेक चीजें जुड़ी हुई हैं और आप उन सब के साथ इसका सम्बन्ध बैठाइये और फिर इन बैंकों के बिजनेस को रिजर्व बैंक के द्वारा जिस आधार पर रेगुलेट किया जा सकता है वह करिये । हां, यह बात सच है कि क्रेडिट-वर्दीनैस का एक प्रश्न निश्चित रूप से विचारणीय था । क्रेडिट-वर्दीनैस की परिभाषा बदल

कर, क्रडिट-वर्दीनैस की परिभाषा में आज की उसकी साख कितनी है, इसका विचार न कर के जिस रुपये को उसे एडवांस कर रहे हैं, जिस रुपये को जिस प्रोडक्टिव परपज के लिये वह लेना चाहता है, उस प्रोडक्टिव परपज के बाद उसकी क्रडिट-वर्दीनैस क्या होगी, उसको भी हम दिये जाने वाले एडवांस में, लोंस में शामिल कर के देखें और वह उस आधार पर कर्जा ले सके, इस स्थिति को हम ला देते तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा अन्तर ऐसे सब लोगों को मदद देने के लिये उसमें से पैदा होता, परन्तु आज केवल इतना कि गरीब लोगों को मदद देने मात्र की इच्छा रखना ही इस सारी समस्या का समाधान नहीं करता, हमें इस देश के सारे रिसोर्सेज और डिपाजिट्स के साथ सारे एडवांसेज का कोई न कोई ताल-मेल बिठाने की आवश्यकता है और इसलिये यह जरूरी है कि इन सब बातों का विचार करना चाहिये ।

मैं इस बात के लिये तो मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बैंक संचालन कानून की धारा 36 ए-डी में बैंक कर्मचारियों पर बैंक प्रिमिसेज में डिमांस्ट्रेशन करने की जो पाबन्दी थी, उसको उठाने का उन्होंने वचन दिया है, परन्तु अच्छा होता अगर वह साथ ही साथ वह कानून भी इसी समय लागू कर देते, क्योंकि सरकार के वायदों पर विश्वास और उसके लिये इंतजारी करने की उन्होंने अपनी साख कम से कम उठा दी है ।. . . और इसलिये अब आगे के वायदों पर आज उनको किसी तरह की बधाई दी जाय इसके लिये मैं तो उनको बधाई नहीं दे सकता । लेकिन अगर वह इस बात के प्रति कमिटेड हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द उस प्रकार की चीज यहां पर लानी चाहिये । मैं इसमें यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने यह जो बात कही कि यह जो अधिगृहित बैंक है । यदि वे चाहें तो किसी पार्टी की साल्वेन्सी देख कर या किसी व्यक्ति का अच्छा साथी देख कर, चाहे वह राजनैतिक नेता हो, चाहे वह राजनैतिक पार्टी या चाहे और हो क्यों न उसको लोन एड्वान्स करें । मगर मैं समझता हूं यहां पर राजनैतिक पार्टियों को कारपोरेशन्स के द्वारा मिले चंदों के बारे में चर्चा हो चुकी है, उसी के परिणाम से हमने कारपोरेशन को मना किया कि वह उसको पैसा नहीं दे सकते । आज जिसको राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं, उन बैंकों पर इस प्रकार चंदे की पाबन्दी की व्यवस्था न कर के शायद आप सरकारी, आड़ में इस भ्रष्टाचार को पनपाने के पक्षपाती हैं, इस बारे में उसकी कोई व्यवस्था किसी तरह से नहीं की गई है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should wind up.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : I am just doing it. I have not much exceeded my time. I am just finishing.

एक दूसरी चीज जिसके बारे में आलोचनाएं हुई, मैं यह मानता हूं कि इन्डस्ट्रियल फील्ड में मोनोपोलीज नहीं बननी चाहिये और क्रेडिट एजेन्सीज को उन मोनोपोलीज की ही सेवा करने का ही साधन नहीं बनना चाहिये, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण मात्र से इस समस्या का समाधान नहीं होता । सरकार के खुद के लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन के फन्ड्स का या और सरकारी साधनों का उपयोग जिस तरीके से इन इन्डस्ट्रियल मोनोपोलिस्ट्स के वास्ते पिछले दिनों में हुआ है, उसको देखते हुए केवल राष्ट्रीयकरण उस बीमारी को दूर नहीं करेगा । उसके लिये हमें सारी लाइसेंसिंग पालिसी को और इन्डस्ट्रियल क्षेत्र में सारी मोनोपोलीज को समाप्त करने और सारे उद्योगीकरण के नक्शे को बदल कर चलना होगा । इस प्रकार उद्योग के क्षेत्र में लगने वाला पैसा अंततोगत्वा जाकर, मोनोपोलिस्ट्स के हाथों में जाकर, इकट्ठा न हो जाय, इसकी व्यवस्था अन्य कारणों से करनी पड़ेगी और केवल सरकार यह सोचे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण मात्र से वह देश में मोनोपोली को रोक पायेगी—अगर दूसरी नीतियों में परिवर्तन नहीं हुआ, देश के औद्योगिक नक्शे में बदल नहीं हुआ, अगर विकेन्द्रित औद्योगीकरण की तरफ सरकार न गई और बड़े लोगों

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

को ही नये लाइसेन्स देने के मामले में पाबंदिया नही लगाई गई—तो फिर उस सवाल को हम ठीक प्रकार से हल नही कर सकेंगे ।

इन सब बातों के आधार पर मैं चाहूंगा कि यह सदन कम से कम इस आर्डिनेन्स को निरस्त करे, इस आर्डिनेन्स को निरस्त करने का मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे । बिल को मंत्री जी शायद प्रस्तुत करने वाले हैं, बिल के आधार पर हम विचार करें और आर्डिनेन्स की लटकती हुई तलवार में इस बिल पर विचार करने के लिये वह मजबूर न करें । मेरा यही कहना है कि इस बिल के प्रति न्याय किया जाय ।

उपसभापति जी, मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि यद्यपि इस बारे में जो फैसला किया हो, लेकिन आप इस बिल पर होने वाले विचार विमर्श में समय-समय पर समय मर्यादा की कुठारी लगा कर सदस्यों को अपने विचारों को ठीक प्रकार से उपस्थित करने में बाधा न डालें और ऐसा कहते हुए मैं फिर चाहूंगा कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

श्री उपसभापति : भंडारी जी ने कहा सदस्यों के भाषण में कुछ बाधा नही डाली जानी चाहिये, लेकिन पहली बार ही इस पर काफी बहस हो गई है. . .

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : कोई सदस्य अगर नहीं बोलना चाहे तो मैं ज़बर्दस्ती किसी को नहीं चाहूंगा ।

श्री उपसभापति : . . .इसलिये मैं समझता हूं अन्य सदस्यों को रात 10 बजे तक तकलीफ दिये बगैर, अगर आप अपने विचार मर्यादित रखते है, तो हर एक को बोलने का मौका मिलेगा और साथ साथ समय से पहले भी हो जायेगा ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभापति जी, अब मन्शा साफ हो गई है ।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. GOVINDA MENON) : Mr. Deputy Chairman, I move :

> "That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of certain banking companies, having regard to their size, resources, coverage and organisation, in order to control the heights of the economy and to meet progressively, and serve better, the needs of development of the economy in conformity with national policy and objectives and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, in making this motion I also want to oppose the resolution just now moved by Mr. Bhandari. As a matter of fact, Sir, I have often felt that when after issuing an Ordinance the Government comes to Parliament with a Bill to replace the Ordinance, a resolution disapproving the Ordinance, seems to be not at all relevant.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Not relevant? What is this? They are two different issues joined together just for expediency.

SHRI P. GOVINDA MENON : I say that it is not relevant because it is irrelevant.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : That logic need not be explained.

SHRI P. GOVINDA MENON : To oppose this Bill is to disapprove of the Ordinance, and if the Bill is not passed, the Ordinance falls down. It is true that in the Constitution there is a provision that Parliament may disapprove of an Ordinance, but when the Government after an Ordinance is issued and as soon as Parliament meets comes with a Bill to replace the Ordinance, I thought that the way to oppose the Ordinance was to oppose the Bill, because if the Bill is not passed, the Ordinance falls down. The only advantage is that the mover of the resolution gets the first chance to speak. I do not regret it, let him have that concession. I do not regret it.

Since this Bill was discussed at length, I mean a similar Bill, in August last year in this House, a lengthy speech by way of explaining the provisions of the Bill does not appear to be necessary. But certain essential things I would like to draw the attention of the House to. As soon as the Ordinance was

issued on the 19th July and as soon as the Bill became an Act on the 9th August, a series of writ petitions were filed in the Supreme Court and till the 10th of February this year the Supreme Court was considering those writ matters. What is it that the Supreme Court has decided? That I want to place before this House. The Supreme Court has summarised its findings towards the end of its judgment and I would like to read that here:

"Accordingly we hold that—

(a) the Act is within the legislative competence of the Parliament, but

(b) it makes hostile discrimination against the named banks in that it prohibits the named banks from carrying on banking business, whereas other banks—Indian and foreign —are permitted to carry on banking business, and even new banks may be formed which may engage in banking business;

(c) it in reality restricts the named banks from carrying on business other than banking as defined in section 5(b) of the Banking Regulation Act, 1949;

(d) the Act violates the guarantee of compensation under article 31(2) in that it provides for giving certain amounts determined according to principles which are not relevant in the determination of compensation of the undertaking of the named banks and by the method prescribed the amounts so declared cannot be regarded as compensation.'

Since the Supreme Court has held that the Act is within the legislative competence of Parliament and has only pointed out certain defects which in their opinion were fatal to the validity of the Act, Government has come with an Ordinance and now with a Bill to replace the Ordinance, which removes the defects pointed out by the Supreme Court. The main question which was being agitated in the Supreme Court was whether a banking undertaking, as an undertaking, can be acquired by Parliament, and that has been answered in favour of the Government, namely, that it is within the competence of Parliament.

Then sub-clauses (b) and (c) are really with respect to the existing banks not being allowed to carry on the banking business while there are other banks in the country which can carry on banking business. This prohibition was contained in section 15 of the Act which was passed in August 1969. We have now taken away that prohibition. We have simply provided for the taking over of the undertakings and left the matter there. If the existing banks think that they would like to continue to do banking business...

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa): On a point of clarification because it is a peculiar position that the Supreme Court has taken. According to this new Bill, the Government of India does not prohibit the earlier bank to carry on banking business. Can they, now after being taken over carry on business in the same old name? Is it possible for them? Is it not a fantastic position that the Supreme Court has created by saying like his?

SHRI P. GOVINDA MENON: I am glad that my hon'ble friend has raised this question. But I do not propose to give a reply here to this question because replying to it it is not necessary for me to pilot this Bill. Just to give an illustration. If the undertaking of the Central Bank of India Limited is acquired by the Government, it will be a statutory corporation created by Parliament. The Central Bank of India Ltd., which continues as a company registered under the Companies Act and the Banking Companies (Regulation) Act...

SHRI A. P. JAIN (Uttar Pradesh): As it is now.

SHRI P. GOVINDA MENON: It is not the question whether they can continue to do banking or not that arises here. We have not said anything regarding that in this Bill. We have taken away prohibition. That is all.

SHRI BANKA BEHARY DAS: And taken away the name.

SHRI P. GOVINDA MENON: That was the Central Bank of India while the other one is the Central Bank of India Ltd. It is open to them to take a decision, after compensation is paid, as to what they would do, whether they would wind up and distribute the compensation among the shareholders, or

SHRI A. P. JAIN: That is what they should do.

SHRI P. GOVINDA MENON :..I do not know—they would like to carry on other business as provided in section 5 of the Banking Companies (Regulation) Act or whether they would approach the Reserve Bank again to give them a licence to do banking with the name, Central Bank of India.

SHRI A. P. JAIN : You have not taken away the licence?

SHRI P. GOVINDA MENON : Yes. But the licence was for a banking undertaking and that undertaking has been taken over.

AN HON'BLE MEMBER : This is a good circle.

SHRI BANKA BEHARY DAS : This is how we function and the Supreme Court also functions.

SHRI P. GOVINDA MENON : Since the Supreme Court said that the prohibition contained in the previous Act against these banks in continung to do business etc. is a hostile discrimination we have removed that discrimination and, therefore, that charge against this Bill will not be available there.

Then there is the question of compensaion. I want to remind the House that sometime in 1955, in then Prime Minister, Panditji, moved an amendment to the Constitution, known as the Fourth Amendment to the Constitution, which had many objects, but one of which alone is relevant here. And that is, the introduction of a clause under article 31(2) which provided that the compensation fixed by legislation by Parliament shall not be justiciable. This is a matter well known to all of you. I do not want to read out from the Constitution. Even before that it was thought that it is not for the court to go into this question, and that was the opinion given by the learned jurists during the Constituent Assembly itself when this particular clause was being discussed. Before the Fourth Amendment of the Constitution the Supreme Court had to observe in a case known as the Bela Banerjee case and compensation was then provided in a Bengal Government Act. But that was not compensation but a just equivalent of the property taken. So the Bill was struck down. Therefore, the anticipation of the founding fathers of the Constitution was that even without the amendment, aricle 31(2) would prohibit a discussion in the court regarding the adequacy or otherwise of the compensation. In spite of that it was laid down by the Supreme Court in its wisdom that compensation means a just equivalent of the property taken over. Now that created difficulties for the Government because whereas the Fundamental Rights chapter in the Constitution lays down the fundamental rights of individuals and one of two clauses about communities, there is another part of the Constitution called the Directive Principles, which lay down fundamental duties on the part of the administration. That is the meaning, according to me, of the Directive Principles. Although they are not justiciable, it has been stated that they are of fundamental importance. It is necessary that Members of Parliament bear this in mind because this is a direction to the Government and Parliament. I will read out article 37. It says :—

> "The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

And the word "State" has the same meaning as is given in article 12. That is to say, "the State" includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under he control of the Government of India. It is a very wide definition.

So from my reading article 37 you would see that the Directive Principles are really laying down fundamental duties of the Government. That is how I would like to put it. No doubt it is said that it is not enforceable by any court; I have been thinking about the meaning of those particular words there. It only means that although these fundamental duties are laid down, it will not be open to a citizen to go to a court and ask for a mandamus against the Government to do a certain thing. For example, there is an article on compulsory primary education of boys and girls up to the age of 14. Take one illustrative example. Supposing in a certain State there has been made no provision by the Government for that purpose. The words in article 37,

"shall not be enforceable by any court" means only this that it is not open to any person, citizen or body of persons to approach the Supreme Court or the High Court for a writ of mandamus against the Government to do a certain thing in a certain manner. But that does not in any way detract from the importance of the Directive Principles. For discharging the duties of Government in the Directive Principles, it may even become necessary to acquire property for many purposes. Now, this banking property is being acquired . . .

SHRI A. P. JAIN: Banking undertakings.

SHRI P. GOVINDA MENON: . . . banking undertakings which is property—is being acquired because, according to Government's policy, there should be a change in the banking policy by which the weaker sections of the community, who have not been getting any assistance from the banks hitherto, should also be enabled to get assistance from these banks. Therefore, it was thought that these 14 banks, which are the biggest among the existing joint-stock banking companies, should be taken over as statutory corporations with a power vested in Government to guide their policies and to direct their policies. That is why a Bill was brought last time. But in that Bill, the provision was not for a fixed amount of compensation, but certain principles regarding fixation of compensation were given in the Second Schedule. The Supreme Court does not agree that the principles given there are good principles, relevant principles and it has said that compensation arrived at according to those principles will not be compensation as contemplated by article 31(2). Now, Sir, I would like to say here on behalf of the Government, and may I say, Sir, on behalf of Parliament, that the word "compensation" in article 31(2) cannot have the same meaning as was given to it in Bela Banerjee's case by the Supreme Court because of the Fourth Amendment. Now, Parliament did not enact this in vain when it said in article 31(2) "No such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate." But we did not provide for lump sumps by way of compensation. Principles were laid down, and according to the Supreme Court, all principles have not been looked into, etc., etc. I do not want to deal with that matter. An important change made in this Ordinance and in this Bill from what existed previously is that the Second Schedule has been changed. Instead of laying down principles, certain lump amounts are provided against the name of each one of the banks as compensation for the undertaking aqcuired from those banks.

SHRI BANKA BEHARY DAS: On what basis?

SHRI P. GOVINDA MENON: I will come to that. And according to the provision of the Constitution, this law cannot be called in question in any court on the ground that the compensation provided by this law is not adequate. Now the Constitution is the sovereign instrument in this country. Parliament is the creation of the Constitution. The Supreme Court is the creation of the Constitution, and all other bodies in the country are subject to the Constitution. To the extent we in Parliament are controlled by the provisions of the Constitution, to the very same extent the Supreme Court also is controlled by the provisions of the Constitution. Therefore, unless we have legislated in a manner which could be described as a fraud on the Constitution, I do not think it will be possible for the Supreme Court to say that the compensation we have fixed now is inadequate. Now because Parliament has been given this power to fix compensation and because the Constitution has provided that the compensation so fixed shall not looked into by courts as to whether it is adequate or inadequate, the responsibility of Parliament is all the more greater, because Parliament should do things with a sense of responsibility in fixing the compensation. A good deal of trouble has been taken by the Finance Ministry, Banking Department, and the Reserve Bank of India, to look into the various aspects of these 14 various banks and that way, these figures have been arrived at. Because it should be possible for the House to know what those figures are, I would just read out—and not simply give it extempore—a statement. . .

SHRI A. P. JAIN: They are printed with the Bill.

SHRI P. GOVINDA MENON: That is the amount. I will give you how we have arrived at that amount. I do that

[Shri P. Govinda Menon.]

because Parliament should have the satisfaction that it understood the principles upon which the compensation was fixed. That is why I read out here the statement prepared for this purpose.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI D. THENGARI), in the Chair]

"On the question how compensation should be given for property acquired for a public purpose, article 31(2) of the Constitution lays down two alternative ways, either of which can be followed to the exclusion of the other. One way is that the amount of compensation should be fixed in the law itself which is made for acquisition of property. The other way is that the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given, should be laid down in the law. In the Act passed in August 1969 for the acquisition of the 14 banking undertakings, the second of the two alternative ways was followed. That Act was struck down by the majority judgment of the Supreme Court on February 10. In the Bill now before Parliament, the way followed is the first one, namely, fixing the amount of compensation in the law itself.

It is clear that in following this way, which is authorised by the Constitution, there need not be any description of principles of determination of compensation. Nevertheless, it is essential that the sovereign Houses of Parliament should satisfy themselves that the amounts of compensation shown in the Second Schedule of the Bill are fair and reasonable, arrived at after judicious and careful calculation. The figures of compensation for the 14 banking undertakings shown in the Second Schedule of the Bill for the approval of Parliament have been calculated by Government after taking into account diverse factors relating to each of the 14 banks as on July 18, 1969, as well as on the date of promulgation of the Ordinance, namely, February 14, 1970. It would be an unfair demand on the time, attention and patience of honourable Members in this House if the Government goes into an elaborate description of very complicated details from various aspects which have individual or inter-linked significance and expect the Members to verify these individually. Among the many factors, the figures and projections to which very careful attention has been paid by officers of the Government and officers of the Reserve Bank, who sat together for many hours doing very detailed calculations before reaching the broad figures of compensation, the more important ones deserve special mention. These are—the profits made by each of the 14 banks which happen to fluctuate from year to year; the profits which the banks could reasonably be expected to make in future years had they remained in the private sector after taking into account their increasing expenses on items like salaries, wages, bonuses, gratuities, etc. and other factors like opening of branches, maintaining satisfactory liquidity of resources, raising fresh capital, and so on. Account was also taken of other factors, as, for example, the paid-up share capital of each bank, the net surplus of each bank which after meeting all the customary appropriations have gone into accumulation of resources over the years in the published accounts; the portion or portions of net surplus which according to practices customary among bankers, do not always have to be shown as accumulation of resources or as surplus carried over in the published accounts; the extent to which the resources published and the secrets are *prima facie* matched by cognizable assets. The ultimate result in respect of compensation for each bank is inextricably connected with the secret resources, if any, of that bank and the secret resources vary from bank to bank. Members may like to apply their own test to judge whether the figures of compensation shown against the banks in the Bill are unduly high or unreasonably low. It will be seen that on the face of it, the aggregate of the compensation figures, that is, Rs. 87.40 crores, for the 14 banks which I stated earlier, have been arrived at on the same basis of treatment as between one bank and another, is neither unduly high nor unreasonably low.

2 P.M.

First, a few words about whether the compensation of Rs. 87.40 crores can be regarded as unduly high. For this purpose a comparison of the proposals in the Bill with what happened when the Imperial Bank of India was taken into the public sector in 1955 a few days after the Fourth Amendment of the Constitution took effect, would be relevant. No doubt, the compensation paid was relatable to the average mar-

ket prices of shares, but when crores of rupees are paid out of the public exchequer, it is the substance of the payment that really matters. At the time of the take-over, that is, June 30, 1955, the Imperial Bank had deposits of about Rs. 208 crores and offices numbering about 355. At the time of the take-over of the fourteen banks their deposits were about Rs. 2,626 crores and their offices numbered well over 4,150. The compensation shown as payable in the case of the Imperial Bank was Rs. 19.72 crores. The total compensation payable to the fourteen banking companies is proposed to be Rs. 87.40 crores. In other words, by giving a compensation of a little less than four times, the public sector is getting deposits of about thirteen times and bank offices about 11½ times...

SHRI BANKA BEHARY DAS: What about the paid-up capital when the Imperial Bank was taken over?

SHRI P. GOVINDA MENON: That too is one of the factors being taken into consideration. The other test which honourable Members may like to make is, as I said earlier, whether the compensation proposed of Rs. 87.40 crores is unreasonably low. One need not go into this question at length. The broad public reactions are well known. But Members would also like to bear in mind that an unreasonably low compensation would in the ultimate analysis hit the vast majority who belong to the middle classes and not the wealthy categories. Out of nearly 1,46,000 shareholders of the fourteen banks, particularly the LIC which looks after the interests of about one crores and a half policyholders and the Unit Trust of India which counts for a lakh and a half of unitholders, the LIC and the Unit Trust of India between them hold about 22 per cent of the total paid-up share capital of the fourteen banks. The compensation figures shown in the Second Schedule to the Bill have been arrived at thus after a judicious consideration of the many relevant aspects of the total situation in respect of each bank. Every one of the fourteen banks has been treated on the same basis.

Now, I read out this because there was a criticism in the other House and there is likely to be a criticism here that whereas we provided only for Rs. 75 crores in the 1969 Bill we have now raised it to Rs. 87.40 crores. I must at once tell the honourable Members that in the previous Bill we did not say that Rs. 75 crores would be the compensation. What we said was that we estimate that it would be of the order of Rs. 75 crores. And we provided for tribunals to be appointed to estimate the value and principles laid down. So, when we said Rs. 75 crores in our estimate, it may have gone up. And as a matter of fact, in the other House a very enterprising Member read out from a magazine, "The Commerce", saying that if the principles are applied and the compensation fixed, according to those principles, it may go up to Rs. 150 crores. A Member even wanted to move a privilege motion against me for misleading the House saying that it is only Rs. 75 crores. Now, that is the position.

Therefore, apart from following an alternative method provided in Article 31(2) we have not simply stated, "Oh, last time it was Rs. 75 crores; but the Supreme Court struck down the law. Let us make it Rs. 87 crores.' That is not the line which has been taken. With respect to the provisions of the Act nobody knew what would be the compensation because it is ultimately the tribunals which will decide that. And the evaluation which the tribunals will give to the buildings, the advances, and to all kinds of properties in a bank, may have variations; we do not know. Even the three Members of the tribunal sitting there may disagree amongst themselves; we do not know. But we would have been bound by that...

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh): You included goodwill also earlier. You say that it is merely a calculation.

SHRI P. GOVINDA MENON: No, the Bill is before you. Goodwill according to me and according to the Government was the least important among those things. But we do not go there.

Therefore, this is a new approach which has been taken in this Bill, that is to say, with the expert guidance of the Reserve Bank of India and with the experts in the Finance Ministry, looking into all the various factors relating to a bank, we fixed certain amounts. And so, if as I hope, this House will vote this Bill into law today, we also know what the amount is which will

[Shri P. Govinda Menon.]

have to go out of the public exchequer for taking over these undertakings. In that respect this Bill is an improvement on the previous Act. When I seek your support for passing this Bill, it is my duty to tell you what has been achieved during these few months when the banks were under public control. In doing so I would like to draw your attention to the fact that as soon as the first Ordinance was issued, two Members of Parliament rushed to the Supreme Court, filed writ petitions and got stay orders with respect to certain matters. As soon as the Ordinance was repealed and the Act was enacted, then again writ petitions were filed and there was a stay. The stay was with respect to a matter of great vitality to the Government, that is to say, the power which was vested in the Government to issue directives regarding policy to the banks. The object of having that provision was to see that the banks would do things in a certain manner so as to benefit the weaker sections of the community. Now we could not issue those directives.

SHRI A. P. JAIN: May I seek a clarification? Was the Order of the Supreme Court confined to the issuing of directives other than those contained in the socialisation of banks Act to some other thing?

SHRI P. GOVINDA MENON: I have got a copy of the Order. I will read it out. It says:

> "...UPON persuing the said Petitions and application and the accompanying documents AND UPON hearing Counsel for the parties and upon Mr. Niren De Counsel for the Respondent herein giving an assurance to the Court that the provisions of section 13 (2) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 will not be enforced pending the hearing and final disposal by this Court of the Writ Petitions above-mentioned; THIS COURT DOTH record the said assurance and DOTH while directing the issue of Rule Nisi returnable before this Court on the 27th October 1969 in both the Writ petitions ORDER (1) THAT removal of any custodian pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1969 referred to above during the pendency of the Writ Petitions above-mentioned be and is hereby stayed and that no direction shall be given by the Government of India contrary to the provisions of section 35(a) of the Banking Regulation Act 1949 as amended by Banking Laws Act 1968 pending the hearing and final disposal by this Court..."

So, certain directions which the Government wanted to issue to these banks could not be issued on account of this stay order. But even in spite of that, what is it that has been done? What has been done during these 5 or 6 months when the banks were under public control?

I think before requesting the House to vote for this Bill I should give some statistics regarding the improvements in this direction which took place. First of all I would refer to the deposits. Last time, Sir, when the Bill was discussed in Parliament, those who opposed it said that as soon as nationalisation takes place there will be a flight of deposits from the nationalised banks to other banks. But what is the position? With respect to these 14 nationalised banks, on the 19th July, 1968 the total deposits were Rs. 2,233 crores. In January 1969 they were Rs. 2,372 crores when the banks were in the private sector. Then in July 1969 they were Rs. 2,626 crores and by the end of the year they were Rs. 2,786 crores. Even during these four or five months when the banks were under State control there has been an enhancement in the deposits and the depositing public did not have its confidence shaken in the nationalised banks, in spite of the fears expressed by certain Members on the floor of the House. Even then I said that there was absolutely no scope for those fears, because in 1955 we nationalised the Imperial Bank of India and called it the State Bank of India and in 1958 or in 1959 seven or eight banks in the Princely States were nationalised and made subsidiaries of the State Bank of India. I asserted last time that the depositing public would have its confidence in the nationalised banks and I had no reason to fear that these 14 banks after nationalisation would show a decline in deposits; they only went up.

Then it was said, Sir, that one of the objects of nationalisation was to provide to agriculture more money from the banking institutions and I must

here say that the number of accounts of agriculturists in June 1969 was 134849 and by the end of the year it went up to 249799.

SHRI BANKA BEHARY DAS: What is the percentage?

SHRI P. GOVINDA MENON: I would like to go step by step. I am trying to take you through a jungle of figures; therefore I should be slow and not jumble figures together.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Anything new that you have not said in the Lok Sabha?

SHRI P. GOVINDA MENON: The day before yesterday I spoke in the Lok Sabha. If you permit me, I will place a copy of my speech in the Lok Sabha. Will that be sufficient?

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: We would like to hear something new.

SHRI P. GOVINDA MENON: Within these two days what new things can I develop?

SHRI BANKA BEHARY DAS: Let us nationalise all banks instead of only these 14 banks. This will be a new thing.

SHRI P. GOVINDA MENON: Sir, I cannot for the sake of novelty produce more things here. I gave only certain relevant figures there. Because that was the House to which I belonged I spoke there first. And here I come as a Minister and give the same arguments which I adduced there. (*Interruptions*) I shall not be doing honour to this House by saying, "I have said everything in the Lok Sabha the other day. Please read those debates of the Lok Sabha." That would be showing scant courtesy to this House. (*Interruptions*) Yes, it may be a breach of privilege also.

Now I will give the figures regarding indirect finance provided to agriculture, and the indirect finance covers advances for distribution of fertilizers and other inputs, advances to State Electricity Boards and other types of indirect finance such as advances to custom service units and co-operative institutions financing agriculture. The number of Accounts in June 1969 was 4047, and by the end of December it was 14053. From a figure of about 4000 it went up to about 14000.

It was asked, Sir, in support of the Bill, by the Members of the ruling party and the other Members of the House, whether by virtue of this nationalisation the small-scale industries will be supported by the advances given from these banks. I would like to give you the figures regarding the advances to small-scale industries also. In June 1969 these 14 banks together had 36,301 Accounts from the small-scale industrialists, and by the end of the year the number went up to 46,512. (*Interruptions*) Now don't think of high figures. I can give you those figures also, but as a socialist I would like to see that there are more Accounts and the amount of each advance is less. What do I care if a big capitalist takes a loan of Rs. 15 lakhs and Rs. 20 lakhs? The small men, the agriculturists, etc. take small loans, and that is what we should encourage. Otherwise, they would have had to go to the pawn-brokers and moneylenders in the villages and pay usurious interest.

Then Advances to Road Transport Operators. We said, Sir, that by nationalisation we would be able to help the self-employed workers, who may run a lorry or ply a taxi or a scooter or a motor rickshaw, etc.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): On a point of clarification. But that would be in the private sector again. Would you encourage that, or would you prefer to encourage if any nationalised road transport undertaking applies for loan from the nationalised banks? What would you prefer between the two?

SHRI P. GOVINDA MENON: There is no question of preference. These 14 banks will have ample resources, and we will give alike to nationalised motor transport companies and to private companies because this private transport is also run by the citizens of this country and it has to be helped. Sir, in June 1969, from the road transport operators there were 2527 Accounts, and by the end of December 1969 they went up to 5067 Accounts. From about 2500 to about 5000 it has doubled. I would also like to give here the advances to taxi drivers, scooter drivers and auto rickshaw drivers because that is very important. They are the smallest men among self-employed people. In June 1969 the number of Accounts belonging to this category, that is, persons having their

[Shri P. Govinda Menon.]

own taxis, persons having their own scooters and persons having their own auto rickshaws, was 2147. And it went up to 4289 in the course of four or five months.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Two thousand more rickshaws have been provided.

SHRI P. GOVINDA MENON: It was also said, Sir, that the banks in the private sector, as they were functioning till that time, utilised their finances to help wholesale traders, big traders, exporters, importers, etc. On behalf of Government and on behalf of the supporters of the Bill it was stated that we would like to see that retail traders, who are generally small people, should also get money from these nationalised banks. And I would like to give some figures regarding their Accounts. In June 1969 the number of Accounts of retail traders in these 14 banks was 28037. By the end of December it went up to 41073.

Then, Sir, another point which we might say in the face of the mounting unemployment in this country is that there are very many educated people, particularly engineers, technicians, etc., who could employ themselves in some industry, trade or business if they could only get the money. There may be a good mechanical engineer who may like to try his hand in fabricating something. But what is it that prevents him from doing it now? He does not get the finance because, if he goes to the bank, he has no gilt-edged security to pledge with the bank. Thus his credit-worthiness is not there. In June 1969 there were only 422 advances to self-employed persons by the joint stock banks of which 421 where from the Bank of Maharashtra and 1 from the Dena Bank. And against all the other banks the entry was nil. That was the position in June 1969. By the end of December 1969 the number went up from 42 to 3029. *(Interruptions)*

Then, Sir, we told the House and the supporters of the Bill also suggested that these banks should give credits to students for higher education and all that. In June 1969 there were 594 Accounts of Advances to students. And this 594 was made up of advances from 6 banks. Out of the 14 banks, 6 banks alone had done this job. But by the end of December 1969 this 594 went up to 1193.

Then I want to give you, Sir, the total advances—that was suggested by somebody—to agriculture, etc. And what is the amount which has been given? in June 1969...

SHRI LOKANATH MISRA: In the other House one of the members of the ruling party alleged that out of an advance of Rs. 5000, Rs. 700 evaporated in the process of giving that loan. Have loan agencies been set up on behalf of the Government for evaporation? Would the hon. Minister explain that point to us?

SHRI P. GOVINDA MENON: I will first of all with the very effluent liquid which I have in my possession of these facts and figures and later on I will speak about evaporation of that thing.

Sir, the total advances of these 14 banks to agrirulture and other neglected sectors of the economy...

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं । जब मंत्री जी इस तरह की फिगर दे रहे हैं, तो उन्हें उनका नाम और पता भी देना चाहिये कि किन-किन विद्यार्थियों को कितनी-कितनी रकम दी गई है, इन विद्यार्थियों का मंत्रियों के साथ क्या संबंध है और कौन मंत्री इन विद्यार्थियों के फूफा, मामा, ससुर, भाई, भतीजे इत्यादि हैं । जब इस तरह से सदन का समय मंत्री जी नष्ट कर रहे है, तो हमें भी पूरे फिगर्स चाहियें कि किन-किन विद्यार्थियों और किन-किन एग्री कलचरिस्टों को यह लोन दिया गया है । इस तरह का जो लोन दिया गया है, उनका पूरा नाम व पता देना चाहिये और यह भी बतलाना चाहिये कि किस-किस को कितना-कितना रुपया लोन के रूप में दिया गया है । हमारा यह चार्ज है कि जिस समय सरकार ने इन बैंकों को अपने हाथ में लिया है, तो उसने इनके रुपये का मिसयूज किया है । इसलिये हम चाहते हैं कि मंत्री जी यहां पर पूरे फिगर्स दें । मंत्री जी यहां पर अधूरी बात बतला रहे है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जिन आंकड़ों को पढ़ा है, उसके साथ ही साथ उन विद्यार्थिय

के नाम भी बतलाये, उन कृषकों के नाम भी बतलायें, उन रिक्शा वालों के नाम बतलायें, उन टैक्सी वालों के नाम बतलायें तथा उनका पूरा पता बतलायें कि हर एक को कितनी कितनी रकम दी गई है ।

SHRI P. GOVINDA MENON : I am sorry, Sir...

श्री राजनारायण : इसमें साडी नहीं होना चाहिये, इसमें धोती होना चाहिये ।

SHRI P. GOVINDA MENON : Sir, with great respect to the hon. Member I must say I have not got the information about the thousands of loantakers etc. Even if it is there, where is the time?

श्री राजनारायण : संसदीय प्रथा में यह, बिलकुल कायदे की मांग है कि जब मंत्री जी एकाउन्ट दे रहे हैं, तो हम यह चाहते है कि जो चार हजार, तीन हजार और पांच हजार की रकम दी गई है, वे किन लोगों को दी गई है और उनके नाम तथा पता क्या क्या है । अगर माननीय मंत्री जी इस तरह से उनके नाम व पता नही बतलायेंगे, तब तक इस सरकार की बेईमानी तथा भ्रष्टाचार पर परदा पड़ा ही रहेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : All right; please take your seat.

SHRI P. GOVINDA MENON : I believe, Sir, the impressive figures which I have reeled out from my notes with respect to what was done in spite of the handicap of the stay order from the Supreme Court during the period 19th July 1969 to the end of 1969 would convince those who had some doubts as to whether nationalisation of these banks would be good or not. I am absolutely certain—I would use the word 'stabilisation' in this respect—that during these six months....

श्री राजनारायण : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंत्री जी को आदेश दें कि वे उन लोगों का नाम व पता बतलायें, जिन्हें बैंकों के जरिये कर्जा दिया गया है । इन बैंकों का रुपया जिस तरह से खर्च किया जा रहा है, उसके बारे में हमें मंत्री जी सूचना दें और यह हमारा अधिकार है कि वे इस तरह की सूचना सदन के सामने पूरी रखें । इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री जी से चाहूंगा कि वे पूरा नाम व पता बतलायें ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बार बार नेशनलाइजेशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि नेशनलाइजेशन का शब्द इस कानून में कही पर भी नहीं आया है । इस विधेयक में यह लिखा हुआ है : बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1970 । यह तो हिन्दी में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में यह लिखा हुआ है :

> The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings), Bill.

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि यह नेशनलाइजेशन नही है, तो फिर इसको राष्ट्रीयकरण नहीं कहा जाना चाहिये । फिर वे किस परपज के लिए बार-बार राष्ट्रीयकरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । आप मंत्री जी को आदेश करें कि जो बिल में कानूनी भाषा लिखी है, उसी भाषा का वे प्रयोग करें । मंत्री जी यहां पर अनावश्यक ढंग से बार-बार राष्ट्रीयकरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । इस तरह से यह राष्ट्रीयकरण शब्द के साथ बलात्कार है और राष्ट्रीयकरण का दुरुपयोग होगा । इस तरह से राष्ट्रीयकरण शब्द का बार-बार प्रयोग करके वे इस देश की भोली-भाली और अशिक्षित जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं । इसलिए आपसे कर बद्ध और हाथ जोड कर प्रार्थना है कि आप मंत्री जी से कहें कि जो कानूनी भाषा है उसी का प्रयोग करें । अगर वे उस भाषा का प्रयोग नही करेंगे, तो यह कंटैम्पट आफ हाउस होगा ।

SHRI B. T. KEMPARAJ (Mysore) : Yes; that is correct.

SHRI P. GOVINDA MENON : I am sorry if I have offended the learned Member by using the word 'nationalisation'.

SHRI RAJNARAIN : You don't know the meaning of 'nationalisation'. Without understanding what is nationalisation he is using the word 'nationalisation'. माफ कीजियेगा कि मेरे मुंह से अंग्रेजी में शब्द निकल गये । माननीय मंत्री जी राष्ट्रीयकरण शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं और इस तरह से अनजाने में राष्ट्रीयकरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ।

SHRI P. GOVINDA MENON : What is purported to be done by this Bill is nationalisation of these fourteen banks. The word 'nationalisation' may be understood in that sense.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar) : Everybody understands this except Mr. Rajnarain.

SHRI P. GOVINDA MENON : I feel certain that..

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, इस बिल में लिखा हुआ है :

> The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1970.

तो मंत्री जी इसको नेशनलाइजेशन कैसे कह सकते हैं, यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं । इस बिल में जो हिन्दी में लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है "बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1970", तो इसको मंत्री जी राष्ट्रीयकरण कैसे कह सकते हैं । अगर राष्ट्रीयकरण हो तो उसमें राष्ट्रीयकरण शब्द लिखा जाना चाहिये ।

एक बात देखी जानी चाहिये कि मंत्री जी यहां पर अंनजाने में जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं । हम इस समय ऊबकर खड़े हुए; क्योंकि हम डेढ़ घंटे से मंत्री जी का ऊबने वाला भाषण सुन रहे हैं । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जानबूझकर सरकार की ओर से गलतफहमी पैदा कर रहे हैं । जनतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और कानूनपालिका इन तीनों की सुपरमैसी होती है । और इन तीनों की सुपरमैसी को मंत्री जी बिलिटल कर रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चीज को राष्ट्रीयकरण नही कहा जा सकता है और उसको राष्ट्रीयकरण नही कहा जाना चाहिये । लेकिन मंत्री जी बार-बार इसको राष्ट्रीयकरण कह कर सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को भंग कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और कानूनपालिका, इन तीनों का अस्तित्व अपनी जगह पर पूरी तरह से कायम रहे । आप कृपया करके माननीय मंत्री जी को इस तरह का आदेश दें कि वे इस शब्द का प्रयोग आगे न करें ।

SHRI P. GOVINDA MENON : On the 8th August 1969 when this matter was put to vote in this House the Bill was passed with a big majority. Now after having seen what we have been able to do during these five or six months after—shall I use the word 'nationalisation'?

SHRI RAJNARAIN : No.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : You better use the word 'acquisition'.

SHRI P. GOVINDA MENON : I hope, Sir, that on this occasion also the House will unanimously vote for this Bill.

Thank you.

SHRIMATI LALITHA (RAJAGOPALAN) (Tamil Nadu) : The Supreme Court in their Judgment have not said that they object to nationalisation of the banks. They have only said that there has been hostile discrimination and Mr. Rajnarain has no right to say that the word 'nationalisation should not be used by the hon. Minister.

(The question was proposed)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) : The Statutory Resolution and the Motion are now open for discussion.